साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Global School Of Excellence, Obedullaganj

Email- thekaarmiicpost@gmail.com

वर्ष : 10, अंक : 51 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 23 जुलाई 2025 से 29 जुलाई 2025 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

2030 तक मप्र का नक्शा बदल देगी यह अर्बन ग्रीन पॉलिसी

भोपाल (एजेंसी)। मप्र सरकार जल्द ही एक ऐसी पॉलिसी लेकर आने जा रही है, जिससे प्रदेश के शहरों का कायापलट होने वाला है। इस पॉलिसी के मंजूर होने के बाद जहां पार्क से लेकर घरों की छत तक हरियाली की चादर नजर आएगी। वहीं इससे वायु और पर्यावरण प्रदूषण भी काफी हद तक रुकेगा। सबसे खास बात यह है कि गर्मी के दिनों में एसी के भारी-भरकम बिल से जूझने वाले उपभोक्ताओं को भी राज्य सरकार की इस पॉलिसी से राहत मिलेगी।

दरअसल शहरों में बढ़ते क्रंकीट के जंगल और कार्बन उत्सर्जन के कारण दिनों-दिन तापमान बढ़ रहा है। इसके साथ वायु और पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ रहा है। इसको नियंत्रित करने के लिए अर्बन ग्रीन पॉलिसी जरूरी है जो हरियाली से संबंधित प्रावधानों को नियमित करती है। मप्र में अर्बन ग्रीन पॉलिसी को लेकर पहले चरण का काम शुरू हो गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और गोवा समेत 12 राज्यों में अर्बन ग्रीन पॉलिसी पहले ही लागू हो चुकी है। बता दें मप्र के शहरों को प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण हितैषी बनाने के लिए राज्य सरकार अर्बन ग्रीन पॉलिसी लाने जा रही है। इसके तहत पार्कों से लेकर छतों तक हरियाली पहुंचाई जाएगी। यह काम शासकीय, सामुदायिक और निजी जिम्मेदारी से पूरा होगा। शहरों में ग्रीन बेल्ट, रूफ टॉप गार्डन, पॉकेट पार्क और स्पंज पार्क तैयार किए जाएंगे। शहर में प्रदूषण के हॉटस्पॉट को चिह्नित कर सबसे पहले इन स्थानों पर हरियाली विकसित की जाएगी। पहले बंजर और हरित जमीन का सर्वे किया जाएगा इसके बाद योजना बनाई जाएगी। लेक्ट्रिकल इंजीनियर देवेंद्र व्यास ने बताया कि यदि किसी घर या कार्यालय के आसपास हरियाली और खुली जगह है, तो परिसर का तापमान नियंत्रित रहता है। ऐसे में एसी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और बिजली कम खर्च होती है। दरअसल पेड़-पौधों की छाया से वाष्पोत्सर्जन होता है, जो हवा का ठंडा करता है। इससे एसी को कम मेहनत करनी पड़ती है। इस प्रकार अर्बन ग्रीन पॉलिसी प्रदेश में अप्रत्यक्ष रूप से बिजली बिल को कम करने में योगदान कर सकती है। शहरों में अर्बन पॉलिसी लागू होने के बाद लोगों को घरों में प्लांटेशन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मियावाकी तकनीकी से रूफ टॉप या वर्टिकल गार्डन तैयार किए जाएंगे। शहरी आवासीय और खाली जगहों पर वृहद वृक्षारोपण किया जाएगा। औद्योगिक पार्क, नदियों के आसपास और फ्लाइओवर के नीचे खाली पड़ी जमीन पर भी पौधरोपण होगा। शहरों में हरित आवरण बढ़ाने के लिए राज्य सरकार विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित करेगी और शहरों को उनके हरित आवरण के अनुसार रेटिंग देगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि प्रदेश की आबोहवा को शुद्ध रखने के लिए अर्बन ग्रीन पॉलिसी जरूरी है। विभाग के केबिनेट मंत्री ने भी इसके निर्देश दिए थे। संविधान के प्रवाधान के अनुसार शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के इंतजाम करने की जिम्मेदारी नगरीय निकायों को सौंपी गई है। ऐसे में प्रदेश सरकार नई अर्बन ग्रीन पॉलिसी बनाने जा रही है। इसका उद्देश्य साल 2030 तक 40 प्रतिशत वायु प्रदूषण कम करना है।

दो दिवसीय प्रबंधन कैम्पिंग प्रशिक्षण सम्पन्न

भोपाल मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा 17 एवं 18 जुलाई को सीहोर जिले के वन मण्डल अंतर्गत ग्राम कठौतिया ईको जंगल कैम्प में दो दिवसीय गंतव्य स्थल प्रबंधन एवं कैम्पिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य ईको पर्यटन स्थल पर कार्यरत समिति सदस्यों को रोजगार के नये आयाम विकसित करना, स्थल पर आने वाले पर्यटकों को वन एवं वन्य-जीव पर्यावरण के संबंध में शिक्षित करना और स्थल के आसपास के सभी गाँवों को वनों को संरक्षित करने के लिये जागरूक करना है। प्रशिक्षण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ईको पर्यटन विकास बोर्ड डॉ. समिता राजौरा ने सभी प्रशिक्षणार्थियों से संवाद किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश के 12 ईको पर्यटन गंतव्य स्थलों, जिनमें सापना ईको पर्यटन स्थल वन मण्डल दक्षिण बैतूल, मगरपाठ व कठौतिया ईको पर्यटन स्थल वन मण्डल सीहोर, बोदाखो व समर्धा ईको पर्यटन स्थल वन मण्डल भोपाल, चिड़ीखो अभयारण्य वन मण्डल राजगढ़, देलावाड़ी ईको पर्यटन स्थल रातापानी टाइगर रिजर्व, उमरीखेड़ा ईको पर्यटन स्थल वन मण्डल इंदौर, देवखो कूनो वन्य-प्राणी अभयारण्य, चारखेड़ा ईको पर्यटन स्थल वन मण्डल खण्डवा, पनपथा ईको पर्यटन स्थल बाँधवगढ़ टाइगर रिजर्व और खिवनी अभयारण्य वन मण्डल देवास से आये कुल 49 सदस्यों, वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन रक्षक, समिति अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सदस्य ने प्रशिक्षण में भाग लिया। ˙ स्वच्छता प्रबंधन, बुनियादी सुविधा, भण्डार प्रबंधन, सुरक्षा प्रबंधन, ट्रेकिंग एवं कैम्पिंग आदि के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। ईको पर्यटन के अंतर्गत गतिविधियों में प्राकृतिक पथ-भ्रमण, पक्षी-दर्शन, विलेज वॉक, रात्रि जंगल वॉक, साहसिक गतिविधि, सेल्फी पाइंट और बैलगाड़ी की सैर इत्यादि शामिल है। प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र भी दिये गये।

सरकार निभा रही हर निवेश संकल्प, टूरिज्म और मेडिकल सेक्टर में मिल रहा बड़ा प्रोत्साहन

इंदौर (नगर प्रतिनिधि)मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश अब केवल संभावना नहीं, बल्कि निवेश का सशक्त मंच बन चुका है। राज्य सरकार ने नीति, प्रक्रिया और प्रोत्साहन के तीनों स्तरों पर गंभीर और प्रभावी सुधार किए हैं, जिससे निवेशकों को वास्तविक लाभ और विश्वास दोनों मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब विकास और निवेश साथ-साथ चल रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विदेश में बसे भारतीय केवल नागरिक ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के संवाहक भी हैं। उन्होंने कहा कि बार्सिलोना में भारतीयों का जो अपनापन दिखा, वह उन्हें उज्जैन की अनुभूति कराता है। भारतीय जहां भी जाते हैं, वहां परंपरा और पर्वों की गरिमा बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल एक संवाद नहीं, बल्कि हृदय से हृदय का जुड़ाव है। सरकार निवेश को केवल आर्थिक लेन-देन नहीं मानती, बल्कि उसे भावनात्मक और दीर्घकालिक भागीदारी का माध्यम मानती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बार्सिलोना में शुक्रवार को प्रवासी भारतीयों और फ्रेंड्स ऑफ एमपी के बीच आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक साख अभूतपूर्व रूप से बढ़ी है। भारत एक मात्र ऐसा देश है जो 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रहा है। यह भारत की क्षमताओं और व्यवस्था की शक्ति का परिचायक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि बार्सिलोना में आप सभी का उत्साह देखकर लग रहा है कि मैं उज्जैन में हूं। काउंसल जनरल श्री इनबासेकर सुंदरमूर्ति के प्रभावशाली भाषण ने दिखा दिया है कि स्पेन के प्रवासी भारतीय आज भी अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। ईश्वर ने भारतीयों को यश दिया है कि जहां चाहें उसे ही स्वर्ग बना देते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन का गौरवशाली इतिहास रहा है। भारतीयों को देखकर लोग होली-दिवाली मना लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतवंशियों की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारतीय, दूध में शक्कर की तरह घुल-मिल जाते हैं। ये देश है वीर जवानों का... भारतीय संस्कृति को दिखाता है। भारत वीरों का देश है। वर्तमान समय में भारत ने दुनिया में अपनी साख बनाई है। भारत की प्रगति देखकर दुनिया दांतो तले ऊंगलियां दबा लेती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में निवेश से जुड़ी सभी नीतियां निवेशकों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। प्रक्रियाओं को डिजिटलीकरण और फास्ट ट्रैक स्वीकृति व्यवस्था से जोड़ा गया है। लंदन में एक उद्योगपति को ऑनलाइन आवेदन के तुरंत बाद भूमि आवंटन किया जाना इसी का उदाहरण है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य शिक्षा के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। यदि कोई संस्था या निवेशक मेडिकल कॉलेज स्थापित करना चाहता है, तो सरकार 25 एकड़ जमीन मात्र एक रुपये में उपलब्ध कराएगी। इससे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों तक पहुंच सकेंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि टूरिज्म सेक्टर को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से होटल परियोजनाओं पर सरकार 30 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता दे रही है। यह सहायता 100 करोड़ रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए लागू है, जिससे प्रदेश में विश्वस्तरीय पर्यटन सुविधाएं विकसित हो सकें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में टेक्सटाइल, फार्मा, एग्रो प्रोसेसिंग और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। आईटी उद्योग को छोटे शहरों तक विस्तार देने की दिशा में सरकार सक्रिय रूप से काम कर रही है। हर सेक्टर के लिए अलग-अलग नीति और सहायता संरचना मौजूद है।

मेडिकल शिक्षा में बड़ा विस्तार, लक्ष्य 50 कॉलेज

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि राज्य सरकार ने मेडिकल शिक्षा के विस्तार को प्राथमिकता दी है। वर्तमान में 37 मेडिकल कॉलेज प्रदेश में संचालित हैं और अगले दो वर्षों में इस संख्या को 50 तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इससे प्रदेश के युवाओं को स्थानीय स्तर पर चिकित्सा शिक्षा के अवसर मिलेंगे।

किसानों को मिलेगी सोलर ऊर्जा से राहत

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए किसानों को 3 लाख से अधिक सोलर पंप देने का निर्णय लिया गया है। इससे सिंचाई पर बिजली की निर्भरता कम होगी और किसानों को बिजली बिल से स्थायी राहत मिलेगी। यह राज्य को ग्रीन एनर्जी की दिशा में भी आगे ले जाएगा।

मध्यप्रदेश बना गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश अब गेहूं उत्पादन में पंजाब जैसे पारंपरिक कृषि राज्य से भी आगे निकल चुका है। कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए फूड प्रोसेसिंग इकाइयों और एग्री क्लस्टर्स की स्थापना की जा रही है। इससे किसानों की आय और औद्योगिक विकास दोनों को बल मिलेगा।

राहवीर योजना और एयर एम्बुलेंस ने बढ़ाया भरोसा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सड़क हादसों में घायल व्यक्ति को अस्पताल तक सुरक्षित पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। राहवीर योजना के तहत ऐसे नेक कार्य करने वालों को 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके साथ ही राज्य में एयर एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की गई है, जिससे आपात स्थिति में तेज़ी से उपचार मिल सके। साथ ही सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए आयुष्मान योजना को प्रभावी रूप से लागू किया है। प्रदेश में लाखों आयुष्मान कार्ड धारकों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। सरकारी और निजी अस्पतालों को इस योजना से जोड़ा गया है।

छोटे शहरों में भी आईटी और रोजगार की पहुंच

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश के छोटे शहरों को भी डिजिटल और तकनीकी विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। यहां आईटी इंडस्ट्री स्थापित करने के प्रयास जारी हैं, जिससे स्थानीय युवाओं को पलायन न करना पड़े और उन्हें अपने ही शहर में रोजगार मिल सके।

प्रवासी भारतीयों को निवेश के लिए दिया स्नेही आमंत्रण

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रवासी भारतीयों से आग्रह किया कि वे केवल देखे नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनें। उन्होंने कहा कि सरकार न केवल सुनती है, बल्कि हर सुझाव पर गहराई से कार्य करती है। यह प्रदेश भारत का दिल है और यहां हर प्रयास, हर संबंध का स्वागत है।

चिड़ियाघर में ई-कार को मिल रहा अच्छा रिस्पांस, अब दो से बढ़ाकर करेंगे पांच

इंदौर. शहर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। पहले 52 एकड़ में फैला संग्रहालय अब बढ़ोतरी होने के बाद 53 एकड़ में फैल चुका है। यहां लगभग 70 पिंजरो में 750 से अधिक जानवर हैं। इन्हें देखने के लिए हर माह लाखों पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। इसी के चलते यहां इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड भी बढ़ने लगी है।

प्राणी संग्रहालय में पर्यटक मात्र 80 रुपए में आराम से पूरे चिड़ियाघर में घूमने के लिए कार ले सकते हैं। इसमें हर पिंजरे के सामने 5 मिनट कार को रोका जाता है और संबंधित जंगली जानवर से लेकर अन्य पशु पक्षियों की भी जानकारी दी जाती है। डबल सीटर साइकिल से भी रिस्पांस मिल रहा है। विदेशी तर्ज पर यहां दो व्यक्ति बैठकर एक साथ साइकिल चला सकते हैं। जल्द ही बैटरी चलित कारों में इजाफा करेंगे। दो बैटरी चलित कार की संख्या पांच तक करेंगे। प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया कि कई बदलाव कर रहे हैं। बैटरी चलित कार में इजाफा होगा, क्योंकि इस कार में फायदा लोगों को मिलता नजर आ रहा है। कई बुजुर्ग से लेकर युवा भी इस कार से चिड़ियाघर का सैर सपाटा करते नजर आ रहे हैं। वहीं साइकिल को खास तौर पर युवा पसंद कर रहे हैं। यहां सांप घर, कांच घर के साथ ही शेर बाघ, तेंदुआ, घड़ियाल, बारहसिंगा सहित अब जेब्रा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पूरे चिड़ियाघर में बैटरी चलित कार में कम से कम 45 से 50 मिनट लग जाते हैं, जिसका किराया मात्र 60 रुपए है और चिड़ियाघर का टिकट 20 रुपए है। ऐसे में देखा जाए तो मात्र 80 रुपए के शुल्क से 53 एकड़ में फैले चिड़ियाघर की सैर आराम से की जा सकती है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से इसका फायदा लगातार प्रबंधन को मिल रहा है। यहां पर चल रही ई-कार और साइकिल इको फ्रेंडली होने के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभदायक है। चिड़ियाघर प्रबंधन नए प्रयोग भी यहां पर करने जा रहा है।

भारत सहित कई देशों में सीवर से नदियों तक फैल रहा मिठास का जहर

सॉफ्ट ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड और टूथपेस्ट जैसे %शुगर-फ्री% उत्पादों में इस्तेमाल होने वाली कृत्रिम मिठास अब सिर्फ आपके खाने तक सीमित नहीं हैं। एक नई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि ये रासायनिक मिठासें अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स से होकर नदियों, झीलों और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र तक पहुंच रही हैं। इनकी वजह से पर्यावरण व दूसरे जीव-जंतुओं के लिए खतरा पैदा हो गया है।

वैज्ञानिकों के मुताबिक इनमें से कई 'शुगर-फ्री' केमिकल इतने स्थाई हैं कि इन्हें हटाना करीब-करीब नामुमकिन है।

देखा जाए तो इनका असर केवल जल गुणवत्ता पर ही नहीं, बल्कि जलीय जीवन, पारिस्थितिकी तंत्र और आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ रहा है। यह अध्ययन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी (यूटीएस) से जुड़े वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है, जिसके नतीजे जर्नल ऑफ हैजर्डस मैटेरियल्स में प्रकाशित हुए हैं। भारत सहित 24 देशों पर किए इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में कृत्रिम मिठास की मौजूदगी, उनकी मात्रा में होता बदलाव, और उन्हें साफ करने की क्षमता का गहराई से अध्ययन किया है। अध्ययन से पता चला है कि सुक्रालोज, एसेसल्फेम, सैकरिन और साइक्लामेट दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कृत्रिम स्वीटनर हैं। अमेरिका, स्पेन, भारत और जर्मनी के सीवेज में इनकी मात्रा सबसे अधिक दर्ज की गई है। अध्ययन के नतीजे दर्शाते हैं कि ज्यादातर देशों में गर्मियों के दौरान कृत्रिम स्वीटनर्स की मात्रा 10 से 30 फीसदी अधिक पाई गई, जबकि चीन में यह मात्रा सर्दियों में सबसे अधिक थी। सीवेज के पानी में पाए जाने वाले अन्य कृत्रिम स्वीटनर्स में नियोटेम, स्टीविया, एसेसल्फेम-के और नियो हेस्पेरिडिन डाइहाइड्रोचाल्कोन (एनएचडीसी) शामिल थे।

वैज्ञानिकों के मुताबिक इनमें से कई 'शुगर-फ्री' केमिकल इतने स्थाई हैं कि इन्हें हटाना करीब-करीब नामुमकिन है; प्रतीकात्मक तस्वीर= आईस्टॉक

वैज्ञानिकों के मुताबिक ये कृत्रिम मिठासें, प्राकृतिक शक्कर से अलग होती हैं। इन्हें इस तरह से बनाया जाता है कि यह आसानी से शरीर में नहीं पचती। यही वजह है कि इनका ज्यादातर हिस्सा शरीर में बिना पचे ही बाहर निकल जाता है, और सीधे सीवेज सिस्टम में पहुंच जाता हैं। वहां भी सामान्य ट्रीटमेंट प्रक्रियाएं इन्हें पूरी तरह साफ नहीं कर पातीं। नतीजन यह इन प्लांट्स से होते हुए नदियों, झीलों, समुद्रों तक पहुंच जाती हैं।

अध्ययन में यह भी सामने आया है कि कि सैकरिन और साइक्लामेट को सीवेज ट्रीटमेंट की मदद से हटाया जा सकता है, लेकिन सुक्रालोज और एसेसल्फेम जैसे कृत्रिम स्वीटनर्स को हटाना मुश्किल होता है, जिससे ये साफ किए बिना ही पर्यावरण में फैल जाते हैं।

गौरतलब है कि कृत्रिम स्वीटनर्स को लेकर लंबे समय से स्वास्थ्य पर बुरे प्रभावों की आशंका जताई जाती रही है। इन्हें टाइप-2 डायबिटीज, दिल की बीमारियों और कैंसर से जोड़ा गया है। इसके अलावा, ये जलीय जीवों के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकते हैं।

अध्ययन में पाया गया कि सुक्रालोज जेब्राफिश में जन्म सम्बन्धी विकार पैदा कर सकता है, जबकि सैकरिन की अधिक मात्रा मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकती है। इस बारे में अध्ययन से जुड़े शोधकर्ता प्रोफेसर वांग ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया, सुक्रालोज जैसी मिठासें बेहद स्थिर होती हैं। इनकी रासायनिक संरचना इतनी स्थिर होती है कि ये सामान्य और उन्नत ट्रीटमेंट प्रक्रिया के बावजूद बच जाती हैं और सीधे नदियों-समुद्र में पहुंच जाती हैं। जहां वो जलीय जीवन को प्रभावित करती हैं।

यह खतरा ठीक वैसा ही है जैसा पीएफएएस जैसे %फॉरएवर केमिकल्स% के मामले में देखा गया है, क्योंकि ये केमिकल पर्यावरण और पीने के पानी में जमा हो जाते हैं और जीवों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक इसी तरह, कृत्रिम मिठासें भी पर्यावरण में धीरे-धीरे जमा होती रहती हैं।

माइक्रोप्लास्टिक से फेफड़ों की कोशिकाओं में हो सकते हैं कैंसर जैसे घातक बदलाव

हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक अब सांसों के जरिए फेफड़ों तक पहुंच रहा है, चिंता की बात है कि प्लास्टिक के ये महीन कण धीरे-धीरे फेफड़ों में कैंसर जैसी बीमारियों के बीज बो रहे हैं।

मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ विएना के वैज्ञानिकों ने अपने नए अध्ययन में खुलासा किया है कि हवा में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक के कण ने केवल शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, बल्कि वो फेफड़ों की स्वस्थ कोशिकाओं में कैंसर जैसी घातक जैविक प्रतिक्रियाएं भी पैदा कर सकते हैं।

यह पहला मौका है जब वैज्ञानकों ने दिखाया है कि ये कण न केवल फेफड़ों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, साथ ही उन्हें कैंसर की दिशा में भी धकेल सकते हैं। इस अध्ययन के नतीजे जर्नल ऑफ हैजर्डस मैटेरियल्स में प्रकाशित हुए हैं, जो प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता को एक बार फिर जोरदार तरीके से रेखांकित करते हैं।

माइक्रोप्लास्टिक हमारे जीवन में इस कदर रच बस गए हैं, उन्हें दूर करना आसान नहीं है। प्लास्टिक के यह महीन कण आज धरती पर करीब-करीब हर जगह मौजूद हैं। अंटार्कटिका की बर्फ से महासागरों की अथाह गहराइयों में भी इनकी मौजूदगी किसी से छिपी नहीं है।

यह कण बादलों, पहाड़ों, मिट्टी यहां तक की जिस हवा में हम सांस लेते हैं, उसमें भी मौजूद हैं। हमारा खाना-पानी भी इनसे अनछुआ नहीं रह गया है। इतना ही नहीं माइक्रोप्लास्टिक मानव रक्त, फेफड़ों, दिमाग सहित अन्य महत्वपूर्ण अंगों तक में अपनी पैठ बना चुके हैं। अपने इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने जांचा है कि पॉलीस्टाइरीन (पीएस) से बने माइक्रो और नैनोप्लास्टिक कण फेफड़ों की अलग-अलग कोशिकाओं पर कैसे असर डालते हैं। बता दें कि पॉलीस्टाइरीन वह प्लास्टिक है जो दही के कप, से लेकर खाने की पैकेजिंग जैसी चीजों में आमतौर पर इस्तेमाल होता है। अध्ययन से पता चला है कि फेफड़ों की स्वस्थ कोशिकाएं प्लास्टिक के बेहद महीन (0.00025 मिमी) कणों को कैंसर कोशिकाओं की तुलना में कहीं अधिक मात्रा में अवशोषित करती हैं। इस अवशोषण के बाद कोशिकाओं में डीएनए क्षति, ऑक्सीडेटिव तनाव, और कैंसर से जुड़ी जैविक गतिविधियां बढ़ने लगती हैं, जो माइक्रोप्लास्टिक के स्वास्थ्य से जुड़े खतरों की ओर इशारा करती हैं। स्टडी में पाया गया कि माइक्रोप्लास्टिक के संपर्क में आने के बाद स्वस्थ कोशिकाओं में डीएनए को सुधारने की क्षमता घट गई, ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ा और साथ ही कुछ ऐसे सिग्नलिंग पथ सक्रिय हो गए जो कोशिका की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं।ये सभी बदलाव कैंसर की शुरुआती अवस्था के संकेत के रूप में जाने जाते हैं। अध्ययन से जुड़ी प्रमुख वैज्ञानिक करिन शेल्च के मुताबिक, सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि स्वस्थ कोशिकाएं डीएनए की क्षति को ठीक नहीं कर पा रही थीं, जबकि साथ ही वे ऐसे रास्तों को सक्रिय कर रही थीं जो सामान्यत: कोशिका में वृद्धि को बढ़ाते हैं।हालांकि यह अध्ययन साफ तौर पर माइक्रोप्लास्टिक के खतरों की ओर इशारा करता है, लेकिन इन कणों के लम्बी अवधि में क्या प्रभाव होंगें वे अभी भी स्पष्ट नहीं हैं। यह सही है कि फेफड़े हवा में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक के संपर्क में आने का एक प्रमुख रास्ता माने जाते हैं, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं था कि ये सूक्ष्म कण फेफड़ों की कोशिकाओं पर कैसे असर डालते हैं।अब उपलब्ध आंकड़ों से यह शुरुआती संकेत मिले हैं कि खासतौर पर फेफड़ों की स्वस्थ कोशिकाएं ऐसे बदलाव दिखा रही हैं जो चिंता का विषय हैं। अध्ययन से जुड़े अन्य वैज्ञानिक बलाज डोमे का प्रेस विज्ञप्ति में कहना है, नई जानकारी यह दर्शाती है कि खासकर स्वस्थ फेफड़ों की कोशिकाएं चिंताजनक तरीके से प्रतिक्रिया देती हैं। दिलचस्प बात यह रही कि जहां कैंसर कोशिकाओं पर इन कणों का खास असर नहीं पड़ा, वहीं स्वस्थ कोशिकाएं थोड़े समय के लिए संपर्क में आने पर भी गंभीर रूप से प्रभावित हुईं। वैज्ञानिको के मुताबिक पॉलीस्टायरीन कणों के प्रभाव में आने पर कोशिकाओं की रक्षा प्रणाली भी सक्रिय हो गई। अध्ययन से जुड़ी वैज्ञानिक बुसरा एर्नहोफर के मुताबिक कोशिकाएं अपने एंटीऑक्सिडेंट सुरक्षा तंत्र को सक्रिय कर रही थीं, यह इस बात का संकेत है कि वे प्लास्टिक कणों से होने वाले तनाव से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थीं।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को नहीं मिले बिल, एफआइआर दर्ज

इंदौर (नगर प्रतिनिधि) राजेंद्र नगर क्षेत्र में राशन की कालाबाजारी के शक में ट्रक जब्त किया गया। इसमें 200 कट्टे चावल मिले। इसकी सूचना नगर निगम महापौर परिषद सदस्य मनीष शर्मा व समाजसेवी अर्पित शर्मा को लगी थी। उन्होंने कैट चौराहे पर ट्रक को रोका व पुलिस के सुपुर्द किया। कार्रवाई के दौरान ट्रक में चार लोग थे। दो पूछताछ के दौरान मौके से फरार हो गए। राजेंद्र नगर थाने से सूचना मिलने पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे व कार्रवाई की। यह राशन सार्वजनिक वितरण प्रणाली का होने की संभावना है। ड्राइवर की प्रारंभिक पूछताछ में जब्त राशन व वाहन बेटमा के व्यापारी का होने की बात सामने आई। अधिकारी संभावना जता रहे हैं कि राशन इंदौर से बेटमा व बेटमा से गुजरात भेजे जाने की तैयारी थी। मनीष शर्मा ने बताया, अबरार व मुकेश के विरुद्ध राजेन्द्र नगर थाने में एफआइआर कराई है। खाद्य विभाग से राहुल शर्मा, महादेव मुवेल व अन्य अधिकारी पहुंचे। जांच में यह स्कूलों में सप्लाय होने वाले मिड डे मील योजना के तहत आने वाले राशन होने की संभावना है। ट्रक ड्राइवर के पास से कोई दस्तावेज नहीं मिले, न ही संबंधित राशन का बिल। प्रथम दृष्टया यह पीडीएस का चावल माना गया, जिसके सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008